

कांग्रेस ने जयपुर के राजघराने का नाम भी घसीटा दुराचारी एप्स्टीन प्रकरण में

एआईसीसी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने ट्वीट करके फैलाया कि महाराजा जयपुर, सवाई पद्मनाभ की बीसवीं सालगिरह पर एप्स्टीन के जानकारी, मित्र व सहयोगी ने एक “अलौकिक” जश्न आयोजित किया

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। कांग्रेस ने जयपुर राजघराने पर भारी कीचड़ उछाला। एआईसीसी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने एप्स्टीन के एक दस्तावेज़ को एक्स पर शेयर किया।
“सोमवार, 14 मई 2018 को, एक प्रेषक (जिसका नाम गोपनीय कर दिया गया है) ने एप्स्टीन को लिखा: मैं इस गर्मी में रोम के पास हमारे पारिवारिक किले में जयपुर के महाराजा के जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रही हूँ। यह अलौकिक होने वाली है!!!”
खेड़ा ने बताया, यहाँ जयपुर के जिन महाराजा का उल्लेख है, वे पद्मनाभ सिंह हैं, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता दीपा कुमारी के पुत्र। सूत्रों ने बताया, वर्ष 2018 में रोम में उनका

- पवन खेड़ा की ट्वीट के अनुसार, यह जश्न (पार्टी) एप्स्टीन के मित्र ने अपने रोम के पास स्थित किले में 2018 में आयोजित किया था तथा इसकी सूचना एप्स्टीन को लिख कर भेजी थी।
- पवन खेड़ा की ट्वीट के अनुसार, जश्न की जानकारी तो “टिप ऑफ द आईसबर्ग” है और एप्स्टीन के घराने से संबंध काफी गहरे और पुराने हैं।
- पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि यह सब जानकारी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वैबसाइट: जस्टिस.जीओवी/एप्स्टीन/फाइल्स/पर उपलब्ध है।
- पवन खेड़ा ने दीपा कुमारी, राजस्थान की वित्त मंत्री, जो दस फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगी, को यह चुनौती भी दी कि वे उनके परिवार पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आक्षेप को स्वीकार करें, प्रतिवाद करें या चुपठी रखें, यह उनका अधिकार है। पर, जनता में भारी उत्सुकता है कि उनके पुत्र के जन्मदिन पर आयोजित “जश्न” का बजट कितना था और किसने उसका भुगतान किया।

20वाँ जन्मदिन भव्य तरीके से आयोजित किया गया था, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि दीपा कुमारी जब कल राज्य का बजट पेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार

पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए तीन शर्तें रखी हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पी.सी.बी.) ने इंटरनैशनल क्रिकेट काउन्सिल (आई.सी.सी.) के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए तीन मांगें रखी हैं। इससे पहले पी.सी.बी. ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, भारत के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप 2026 मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था, जबकि आईसीसी ने उसे संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी भी दी थी।
सूत्रों के अनुसार, पी.सी.बी. ने रविवार को लाहौर में आई.सी.सी. अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान गतिरोध खत्म करने के लिए तीन मांगें रखीं: (1) बांग्लादेश के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए, (2) टी20

- पहली शर्त है, बांग्लादेश को ज्यादा हर्जाना दिया जाए।
- दूसरी शर्त है, बांग्लादेश भले ही टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, पर, उसे पूरी फीस दी जाए।
- तीसरी शर्त है, पाकिस्तान को भी भविष्य में आईसीसी का इवेंट आयोजित करने का अवसर दिया जाए।

विश्व कप से बाहर होने के बावजूद बांग्लादेश को भागीदारी शुल्क दिया जाए, और (3) भविष्य में किसी आई.सी.सी. टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार दिया जाए।
सूत्रों ने यह भी बताया कि जहाँ कुछ पी.सी.बी. अधिकारी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच खेलने के पक्ष में हैं, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
आई.सी.सी. ने पिछले महीने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार कर दिया था। आई.सी.सी. ने भरोसा दिलाया था कि टीम के लिए कोई सत्यापित खतरा नहीं है, फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बी.सी.बी.) अपने फैसले पर कायम रहा, जिसके बाद आई.सी.सी. ने उसको जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।

मान को विदेश यात्रा की अनुमति तीसरी बार भी नहीं मिली

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चेक

- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीदरलैंड व चैंक रिपब्लिक जाने वाले थे, पर, केन्द्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। इससे पहले उन्हें यूके व इज़रायल जाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी।

गणराज्य और नीदरलैंड की यात्रा रद्द हो गई है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने उनकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पुरजोर ढंग से कहा था, जो 1.36 करोड़ नाम कटे हैं, उसके लिए अफसर जिम्मेदार हैं, पर, आपने अफसरों के नाम नहीं बताए

- सुप्रीम कोर्ट में प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका की सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने राज्य में एसआईआर को चुनौती दी है और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
- चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अफसरों के नाम नहीं बताए।

विवाह के बाद बेटियों के पते बदलने जैसी त्रुटियों के आधार पर पैदा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि अधिकारियों से संबंधित विवरण और जानकारी साझा नहीं की गई। ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने निर्वाचन आयोग के इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि नाम तैयार हैं, संकलित कर लिए गए हैं तथा उन्हें आयोग को भेज दिया गया था।
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ममता बनर्जी से सवाल किया, “जब हमने 4 फरवरी को निर्देश दिए थे, तो आप 7 फरवरी को रात 12 बजे ई-मेल के जरिए नाम क्यों भेज रही हैं?”

संसद को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली, 09 फरवरी। राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1.11 बजे संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे।
अधिकारियों ने बताया कि आठ धमकियां बाद में फर्जी पाई गईं। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तान बनाने का भी जिक्र था। धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के मुताबिक, सुबह अलग-अलग इलाकों के स्कूलों से इमरजेंसी कॉल आईं। इसके बाद फायर टैंडर, बम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीकेवाईसी आईडी: केवाईसी संबंधी आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाली एकमात्र चाबी



सीकेवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा जारी की जाने वाली 14-डिजिट की विशिष्ट सीकेवाईसी आईडी

यह कैसे काम करता है?

- केवाईसी जानकारी अपने बैंक में जमा करें।
- बैंक केवाईसी जानकारी केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड करता है।
- इसे सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

अपनी सीकेवाईसी आईडी को जानें।

☎ मिस्ट कॉल: 7799022129 या
🌐 ऑनलाइन: www.cvkycindia.in

प्रमुख फायदे

- विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में आसानी से खाता खोलें।
- केवाईसी अपडेट करना हुआ आसान; एक बैंक में अपडेट की गई केवाईसी आपके अन्य सभी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में अपडेट हो जाती है सीकेवाईसी के जरिए।

आसान। सुरक्षित। मानकीकृत।



अधिक जानकारी के लिए
पेज <http://rbi.kshatrahala.org.in>
अथवा कॉल करें के लिए rbi.kshatrahala.org.in पर क्लिक करें।
आधिकारिक वेबसाइट
नं. 99990 41935 / 99309 91935



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

सबसे बुरा तरीका वह था, जिसमें उन्होंने विपक्षी महिला सांसदों के खिलाफ नरेन्द्र मोदी पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। –कहावत

‘ट्रेड डील’ या ‘ट्रैप डील’

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K



डॉ. नीरज रावत

समकालीन भारत एक ऐसे विरोधाभास से गुजर रहा है, जिसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहा। एक ओर हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करता है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में जाति की मौजूदगी लगातार और मुखर होती जा रही है। राजनीति से

लेकर प्रशासन और सामाजिक व्यवहार तक, जाति किसी न किसी रूप में निर्णायक भूमिका निभाती दिखती है। यह स्थिति केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

यह स्पष्ट है कि जाति भारतीय समाज की ऐतिहासिक सच्चाई रही है। इसे नकारना न तो संभव है और न ही व्यावहारिका। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या एक आधुनिक, संवैधानिक लोकतंत्र की राजनीति को हमेशा जातीय पहचान के इर्द-गिर्द ही संगठित होना चाहिए? क्या नागरिक की पहचान उसके अधिकारों, कर्तव्यों और क्षमताओं के बजाय जन्म आधारित श्रेणियों से तय होती रहेगी? स्वतंत्रता के बाद देश के नीति-निर्माताओं की परिकल्पना इससे अलग थी। संविधान ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान किए। इनका

उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना था, न कि उन्हें स्थायी राजनीतिक पहचान में बदल देना। किंतु समय के साथ यह संतुलन बिगड़ता चला गया। सुधार के लिए बनाई गई व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे सत्ता की राजनीति का हथियार बनती जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि जाति की राजनीति सशक्तिकरण से अधिक चुनावी गणित का रूप ले चुकी है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे अक्सर हाशिये पर चले जाते हैं, जबकि जातीय समीकरण चुनावी विमर्श के केंद्र में आ जाते हैं। नीतियाँ और योग्यता पर बहस के बजाय, समाज को छोटे-छोटे खान्चों में बाँटकर समर्थन जुटाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका असर लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता पर साफ़ दिखाई देता है।

यह प्रभाव केवल चुनावों तक सीमित नहीं है। नौकरियों, पदोन्नतियों और संस्थागत निर्णयों में भी जाति का

दबाव महसूस किया जाता है। परिणामस्वरूप योग्यता और दक्षता पर संदेह की स्थिति बनती है, जिससे शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। समाज में आपसी भरोसा कमजोर पड़ता है और नागरिक स्वयं को पहले किसी जाति का सदस्य और बाद में देश का नागरिक मानने लगते हैं। किसी भी आधुनिक राष्ट्र के लिए यह प्रवृत्ति घातक कही जा सकती है। विडंबना यह है कि जाति की राजनीति अंततः उन्हीं वर्गों को नुकसान पहुँचाती है, जिनके नाम पर इसे जायज ठहराया जाता है। लगातार ‘पीड़ित’ की पहचान में बाँधे जाने से आत्मनिर्भरता, उद्यम और प्रतिस्पर्धा की भावना कमजोर होती है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। आज लगता है कि हम उस चेतावनी से सीखने के बजाय, सामाजिक विभाजनों को और गहरा कर रहे हैं।

राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं कि

समाज एकरूप हो जाए, बल्कि यह कि सभी नागरिक कुछ साझा संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार करें। यदि राजनीति का आधार केवल जाति बनता चला गया, तो देश विभिन्न हित-समूहों का ढीला-ढाला गड्‌जोड़ बनकर रह जाएगा। ऐसी स्थिति न तो लोकतंत्र को मजबूत करती है और न ही सामाजिक एकाता को।

अब समय है गंभीर आत्ममंथन का। न्याय का अर्थ केवल संसाधनों का बँटवारा नहीं, बल्कि अवसर की समानता भी है। राजनीति को जाति की संकीर्ण भाषा से बाहर निकालकर संविधान, विकास और नागरिक अधिकारों की व्यापक समझ की ओर लौटना होगा। अन्यथा यह आशंका बनी रहेगी कि संविधान केवल एक आदर्श दस्तावेज़ बनकर रह जाएगा, जबकि उसकी आत्मा धीरे-धीरे कमजोर होती चली जाएगी।

–डॉ. नीरज रावत, लेखक जयपुर

पुस्तक समीक्षा काव्य संग्रह : “ जिंदगी मुस्कुराती रहे”

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक डॉ. लीलाधर दोचानियां गद्य और पद्य दोनों के विधाओं के सशक्त हस्तक्षार है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े लीलाधर की कविताओं में साफगोई झलकती है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में पद स्थापन के दौरान उन्होंने जो देखा, अनुभव किया वही अपनी कविताओं में परोसा। काव्य कृति के रूप में उनकी यह प्रथम पुस्तक है। ॐ

।पने कविता संग्रह में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जीवन की सहज अनुभूतियों और संवेदनाओं को प्रकट करता कविता संग्रह समाज को प्रेक्षित कर एक अनूठा प्रयोग किया है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से सजीव रूप में परोसा गया है। कविताएं अपने व्यक्तिगत अनुभवों की श्रंखला के रूप में आकार लेती हैं साथ ही सामाजिक सच्चाइयों का संचार भी करती हैं।

निश्चय ही रचनाओं में कवि के मन और भावनाओं को सुंदर शब्दों में आकार लिया है।कविताओं में विविध विषयों को सरल शब्दों के माध्यम से संप्रेषित कर एक अनूठा प्रयोग किया है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से सजीव रूप में परोसा गया है। कविताएं अपने व्यक्तिगत अनुभवों की श्रंखला के रूप में आकार लेती हैं साथ ही सामाजिक सच्चाइयों का संचार भी करती हैं।

113 पृष्ठ के इस कविता संग्रह में 96 काव्य रचनाएँ हैं। पुस्तक केवल कविताओं का ही नहीं बल्कि भावनाओं, संवेदनाओं और अभिव्यक्ति का भी सशक्त संग्रह है। सभी कविताएं हृदय को छूने वाली हैं। आशा है कि यह कविता संग्रह पाठकों को पसंद आएगा।

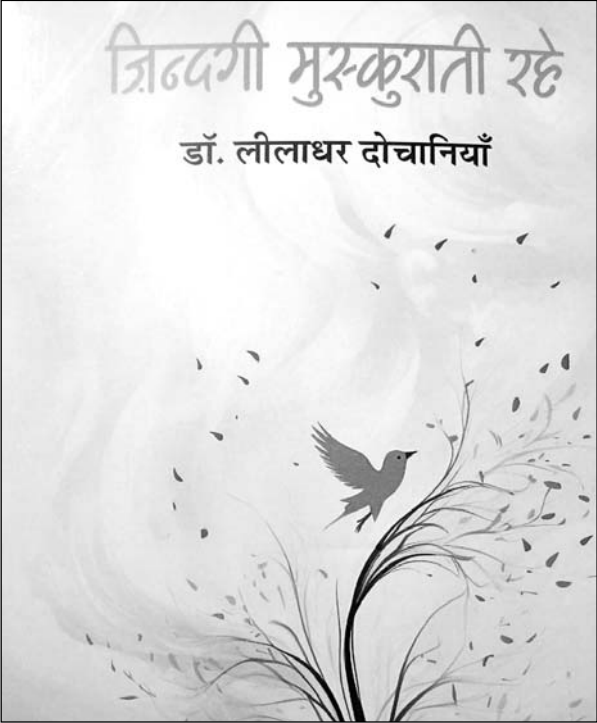
समीक्षक कृति : जिंदगी

मुस्कुराती रहे।

कवि : डॉ. लीलाधर

दोचानियां ।

समीक्षक : बालमुकुंद ओझा



अलवर : सड़क हादसे में लैपर्ड की मौत



वन विभाग टीम ने मृत लैपर्ड का पोस्टमार्टम करवाया।

अलवर, (निर्स)। नारायणपुर क्षेत्र के नांगलहेड़ी गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक लैपर्ड की मौत हो गई। यह हादसा नारायणपुर-कुरुलगाढ़ रोड पर उस समय हुआ, जब अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लैपर्ड की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लैपर्ड के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को तालवृक्ष रेंज कार्यालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों की

टीम की ओर से विधिवत पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की ओर से लैपर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि लैपर्ड प्रथम श्रेणी का वन्यजीव है, जिसकी सुरक्षा को लेकर विशेष नियम लागू हैं।

वन विभाग के रेंजर त्रिलोक कुमावत ने बताया कि मृत लैपर्ड नर था और उसकी उम्र करीब ढाई वर्ष आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में लैपर्ड की मौत का कारण सड़क दुर्घटना सामने आया है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र वन्यजीवों की नियमित आवाजाही

वाला इलाका है और तेज रफ्तार वाहन वन्यजीवों के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं।

कारंबाई के दौरान तहसीलदार अनिल कुमार, वनपाल मनोज नागा, पशु चिकित्सक डॉ. रमेश चंद वर्मा, डॉ. मुकेश सैनी, डॉ. कमलेश सैनी सहित वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। वन अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वन क्षेत्र से गुजरते समय सतर्कता बरतें और वाहनों की गति नियंत्रित रखें, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K

C M K



पंडित अनिल शर्मा

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज अष्टमी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:56 से 11:19 तक, लाभ-अमृत 11:19 से 2:04 तक, शुभ 3:00 से 4:48 तक।

राहूकाल: 3:26 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 6:11

राशिफल

मंगलवार 10 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र प्रात: 7:55 तक, ध्रुव योग रात्रि 1:42 तक, कौलव करण प्रात: 7:28 तक, कार्त्तिक आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज अष्टमी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:56 से 11:19 तक, लाभ-अमृत 11:19 से 2:04 तक, शुभ 3:00 से 4:48 तक।

राहूकाल: 3:26 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 6:11



मेष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।



तुला

आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।



वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृश्चिक

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



मिथुन

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।



धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।



कर्क

परिजन के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।



मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।



सिंह

घर-परिवार में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।



मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सार-समाचार

लड़ते नदियों की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत, नंदीशाला की मांग को लेकर फूटा जन आक्रोश

रतनगढ़, (निसं)। चार फरवरी को देर शाम लड़ते हुए नदियों की चपेट में आकर धायल हुए बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 14, नाइयों के मंदिर के पास निवासी 85 वर्षीय अमरचंद दाधीच 04 फरवरी को बाइक के पीछे बैठकर घर लौट रहे थे। सायं करीब 6 बजे अशोक संतंभ के पास पुरानी आईटीआई के नजदीक लडते हुए नदियों के मोटरसाइकिल से टकरा जाने के कारण वे सड़क पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।धायल अवस्था में उन्हें तुरंत रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया। लगातार हालत गंभीर बने रहने और होश नहीं आने पर उन्हें सीकर से जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन 08 फरवरी को देर शाम उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मौत की सूचना मिली, कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई।सोमवार 09 फरवरी को जालान मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के बाद घटना से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी रतनगढ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जापन में शहर में खुलेआम घूम रहे बेसहारा नदियों के लिए नंदीशाला अथवा अन्य समुचित व्यवस्था करने की मांग की गई। साथ ही शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई।इस दौरान लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपखंड अधिकारी की ओर से यह ज्ञापन तत्सिलदार पूजा पारीक ने प्राप्त किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सीए संवाद सेमिनार आयोजित

सीकर, (निसं)। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सीए संवाद सेमीनार सोमवार हो हुआ। भाजपा के जिला बजट प्रचार अभियान संयोजक सीए श्रीहरि बिजानी ने बताया कि सीए सेमीनार में केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवाओं में बायोफार्मा में मैनुफैक्चरिंग के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। बुजुर्गों और संबद्ध देखभाल सेवाओं के लिए अगले वर्ष 1.5 लाख बहु-कोशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपातकालीन और ट्रोमा केयर सेंटर जिला अस्पताल केंद्रों की क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्र में किसानों को खेती के लिए कस्टमाइज्ड सलाह प्रदान करेगा। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। नारियल संवर्धन योजना में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पुराने पेड़ों को नई किस्म में बदला जाएगा। इसके साथ ही युवा, शिक्षा और खेल, छोटे करदाताओं के लिए सहायता, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण में आजीविका के अवसर प्रदान करेंगा। सेमीनार में जिला बजट प्रचार अभियान संयोजक सीए श्रीहरि बिजानी, सहसंयोजक सीए राजीव लोचन शर्मा, सीए अभिषेक सोनी, सीए शुभम शर्मा, सीए अरुण भास्कर, सीए राजेश गोयल, सीए शुभम अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

सहकारी बैंक शिविर से किसानों को मिला नया अवसर

सीकर (निसं)। सांवलपुरा तंवरान गिरदावर सर्किल में 9 फरवरी 2026 सोमवार को आयोजित कैम्प के दौरान सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबंधित अजमेरी, जुगलपुरा एवं पिपलाटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में यूडीएच मंत्री राखार सिंह खरौं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंचगण, समिति अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। शिविर के दौरान सांवलपुरा तंवरान ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नवीन संविधान की प्रमाण पत्र दिया गया साथ ही नवीन सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया। कृषकों व ग्रामीणों को बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई साथ ही सहकारी समितियों में सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में आने वाले कृषकों को सहकारी समितियों में जुड़ने के लिए सहकारी समितियों में जारी विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से पर्यवेक्षणीय अधिकारी व समिति व्यवस्थापकों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

भोमपुरा में शिव प्रतिमा एवं मोक्ष धाम टीनशेड का लोकार्पण

झुंझुनू, (निसं)। ग्राम भोमपुरा में भामाशाह विद्याधर गिल एवं उनके परिवार के सहयोग से निर्मित भव्य शिव प्रतिमा तथा मोक्ष धाम से निर्मित टीन शैड का लोकार्पण विधाायक राइडर भांबू द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विश्वंभर पूनियां विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही श्री कृष्ण महला, हरपाल सरपंचबीबासर, उमेशशंखरण, राजू चाहर, रामचंद्र गडवाल, सुरेश कुमार शर्मा, मनोज शर्मा भोमपुरा, चंदरसिंह तोडाड़ा खुर्द, मुकेश पातुसरी, भगवाननाम खीचंद एवं बनवारी टेंटर सहित अनेक सहकारी नागरिक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। विधायक राइडर भांबू ने भामाशाह विद्याधर गिल एवं उनके परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक कार्या प्राण विकास के साथ-साथ समाज में सहृदय और सेवा की भावना को मजबूत करते है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी इस पुनीत कार्य के लिए भामाशाहा परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का समापन श्रद्धा, भक्ति एवं सामाजिक समरसता के वातावरण में हुआ।

जागरूकता शिविर आज

सीकर (निसं)। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सीकर महाप्रबन्धक विकास सिंहाण ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा आमजन एवं उद्यमियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11.30 बजे पालडीवाला, आईटीआई एण्ड व्होरेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूटयू, बंजारों की बस्ती के पास, बेरास बासनी रोड, लक्ष्मणगढ, सीकर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाएं यथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना व पॉलिसीयों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान, ऋण सुविधा एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

सुरक्षित इंटरनेट पर जागरूकता कार्यशाला आज

सीकर (निसं)। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त को निर्देश दिये है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में फरवरी माह के दूसरे 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाना है। दिवस की थीम : स्मार्ट टेक, सुरक्षित विकल्प के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की खोज रखा गया है। जिले के समस्त कार्यालयों, राजकीय, निजी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में जागरूकता सत्र आयोजित किये जाने है। जिनमें स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए उन्हें साइबर खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी देनी है।

भाजयुमो की बैठक आज

सीकर (निसं)। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को सुबह 11.30 बजे आयोजित की गई है। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने बताया कि बैठक जिलाध्यक्ष मनोज बाटड के नेतृत्व में होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी पंचायत, निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वर्गों 16 फरवरी को भाजयुमो के प्रदेशध्यक्ष शंकर गौरा के सीकर आमजन पर स्वागत की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में भाजयुमो के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि भाग लेंगे।

मोनालिसा ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया

नोहर, (निसं)। स्थानीय टैगोर चौक के नजदीक मोनालिसा चेरिटेबल ब्लड सेंटर का विधायक अमित चाचाण ने विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान स्वीच्छक रक्तदान का आयोजन भी किया गया जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन मोनिका खटोतिया, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण भाकर, कृषि उपज मंडी निवर्तमान चेयरमैन बलवीर सुमार, पी. एम. ओ.डॉ. हंसराज शर्मा, युवा नेता अनिल पारीक, मनीराम छिम्मा, वरिष्ठ पत्रकार मोहरसिंह,अजय सरावगी भव्य शुभारंभ की साक्षी बने।

डालसा सचिव ने बीडीके अस्पताल के पालना गृह का निरीक्षण किया

झुंझुनू, (निसं)। राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू के पालना गृह का जिला जज दीपा गुर्जर तथा डालसा सचिव एडीजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने निरीक्षण किया गया। पालना गृह की मॉक डील करते हुए पालना के बेड पर वजन रखा तो आपातकालीन इकाई में घंटी बजी तो स्टाफ दौड़ते हुए पालना गृह की ओर आया।

इसी दौरान जिला जज दीपा गुर्जर ने अस्पताल में अब तक आए पालनागृह में बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी ली गई। जिलेभर के सभी पालना गृहों में बीडीके अस्पताल में सर्वाधिक नवजात छोड़े गए हैं तथा परिजनों की पहचान उज्जगर नहीं की जाती है। अस्पताल के मुख्य द्वार, स्वागत कक्ष, नवजात शिशु इकाई, ओपीडी समेत विभिन्न जगहों लगाई गई आईईसी का अवलोकन किया गया तथा बड़ा पोस्टर मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। धूप से फीकी हो रही आईईसी को फिर से प्रदर्शित करने एवं ओपीडी, आईपीडी में आमजन को पालनागृह के बारे में बताने के लिए निर्देशित किया गया। जिला जज ने अस्पताल की साफ सफाई एवं वार्ड आईसीयू की सेवाओं को बेहतरीन बताया तथा बीडीके अस्पताल में जल्द ही वीसी के माध्यम से गवाही करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

नटखट श्याम मंडल सीकर की 13वीं निशान पदयात्रा रवाना

सीकर, (निसं)। नटखट श्याम मंडल सीकर की 13वीं निशान पदयात्रा श्रद्धा व उल्लास के साथ रवाना हुई। नटखट श्याम मंडल सीकर के कमल पटवारी ने बताया कि यात्रा में कुल 55 निशान, 11 चांदी के निशान एवं 151 पदयात्री शामिल हुए।

समिति सदस्य नवरंग अग्रवाल एवं दीपाशु मिलन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 7:15 बजे निशान पूजन के पश्चात गांधी-बाजे के साथ निशान पदयात्री भारत भूरण अग्रवाल के निवास स्थान, ज्ञान भारती स्कूल की गली, राधाकिशनगुरा से रवाना हुए। मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया गया।तात्पश्चात पदयात्री शशांक ऑटोमोबाइल फिटनेस सेंटर



राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू के पालना गृह का जिला जज दीपा गुर्जर तथा डालसा सचिव एडीजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने निरीक्षण किया गया।

शहर में स्थित दो रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया:- इसी तरह जिला जज दीपा गुर्जर तथा डालसा सचिव एडीजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी द्वारा नगर परिषद झुंझुनू तथा पंचदेव मंदिर के पास स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। दीपा गुर्जर ने बताया कि रैन बसेरों के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों में ठहरे हुए निराश्रितों और जरूरतमंदों को मिलने वाली सुविधाओं और कानूनी

अधिकारों की उपलब्धता को जांचना था। डालसा अध्यक्ष जिला जज दीपा गुर्जर ने रैन बसेरों में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, बिस्तरों की स्वच्छता और अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अध्यक्ष दीपा गुर्जर द्वारा रैन बसेरों में रात्रि विश्राम के लिए उपस्थित आने वालों की संख्या काफ़ी कम पाए जाने पर उक्त रैन बसेरों के प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 फरवरी से

सीकर, (निसं)। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि जगणणा 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। इस चरण में स्व-गणना का कार्य 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक तथा फील्ड कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक किया जाना प्रस्तावित है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला एवं चार्ज अधिकारियों का दो दिवसीय तथा नियमित सत्राध्यक्षों का तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण जिला स्तर पर जगणणा कार्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 12 फरवरी से 14 फरवरी 2026 तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार, सीकर में आयोजित किया जाएगा।

यहीं पर साधारण समारोह के रूप में निशान पदयात्रा का समापन किया गया।यात्रा के दौरान प्रेम मंदिर परिसर में स्थित परियट्ट सेल्फी प्वाइंट पर सभी पदयात्रियों ने निर्धारित ड्रेस कोड में एकत्र होकर समूहिक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जो हर वर्ष की परंपरा के अनुसार यात्रा की एक विशेष स्मृति रही।

पानी की व्यवस्थाओं का संचालन किया गया। समिति सदस्य संजय अग्रवाल एवं एल.बी. अग्रवाल ने बताया कि सायंकाल पदयात्रियों के लिए लोहारू धर्मशाला में अल्पाहार की व्यवस्था की गई तथा निशान यात्रा पूर्ण होने पर मंडा मोहा फागुस में रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई।

यहीं पर साधारण समारोह के रूप में निशान पदयात्रा का समापन किया गया।यात्रा के दौरान प्रेम मंदिर परिसर में स्थित परियट्ट सेल्फी प्वाइंट पर सभी पदयात्रियों ने निर्धारित ड्रेस कोड में एकत्र होकर समूहिक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जो हर वर्ष की परंपरा के अनुसार यात्रा की एक विशेष स्मृति रही।

कांग्रेस ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों का सम्मान किया

झुंझुनू, (निसं)। जिले के बगड कस्बे के वार्ड 19 बनिया वाली ढाणी में जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। हाल ही में शाकिर हुसैन को जिला सचिव व अब्दुल रहमान इस्लामगढ़ को ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों पदाधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित कर उनका माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेट्री पीसीसी सदस्य रणजीतसिंह चंदेलिया, विशिष्ट अतिथि दिव्यज्योति लाडब्रेरी के प्रबंधक श्यामलाल सैनी, पूर्व पार्षद सुभाष आल्हा, शुभकरन बरबड, क्यूम लुहार, अहमद मास्टर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद रामनिवास सैनी ने की। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य चंदेलिया ने कार्यक्रम में नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं और

कार्यकर्ता के बल पर पार्टीयां सत्ता में आती हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान मिले। नवनियुक्त जिला सचिव शाकिर हुसैन व ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल रहमान ने भी पार्टी को मजबूत करने की बात कही। रतन आल्हा, मेक मोहम्मद, महेंद्र कुमावत, मोहम्मद अली लुहार, शुभरती, शौकत अली, पूर्व क्रय विक्रय समिति सचिव नथुराम सैनी, इरसाक, जोगेंद्र सैनी, तायर हुसैन, लीलाराम सैनी ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कांग्रेस कमेट्री सदस्य रणजीतसिंह चंदेलिया किया। इस अवसर पर मुस्तफा, मोहम्मद आरिफ, अंजुम लुहार, इरशाद जाकिर, मास्टर असलम तंवर, मोहम्मद अब्बास सहित वार्ड की महिलाएं व कई गणमान्यजन उपस्थित थे।

ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति:- इधर, जिला कार्यकारिणी के बाद जिलाध्यक्ष संतोष सैनी ने प्रदेश

सार-समाचार

‘आयुष्मान भारत योजना में इलाज राशि 20 लाख की जाए’

झुंझुनू, (निसं)। सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता और सीमित इलाज राशि को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि सरकार आज भी योजना की पात्रता वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों पर तय कर रही है। जो वर्तमान सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं से लगभग पूरी तरह से अलग है। 15 वर्ष पुराने आंकड़ों के आधार पर आज के गरीबों की पहचान करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के कारण लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। लेकिन वे आयुष्मान भारत योजना से बाहर हैं। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान में आज भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार गंभीर बीमारी के समय इलाज से वंचित रह जाते हैं और कर्ज, जमीन-जेवर गिरवी रखने या इलाज छोड़ने को मजबूर हैं। सांसद ने कहा कि वर्तमान पांच लाख रूपए की इलाज सीमा आज की अनेक बीमारियों की चिकित्सा लागत के मुकाबले बेहद अपर्याप्त है। निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का खर्च कई गुना बढ़ चुका है, जिससे गरीब परिवारों को फिर से जेब से खर्च करना पड़ रहा है। सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है की आयुष्मान भारत योजना की पात्रता के लिए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग कर वंचित गरीब परिवारों को तुरंत योजना में शामिल किया जाए तथा इलाज सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपए प्रति वर्ष किया जाए। ताकि यह योजना वास्तव में गरीबों के लिए संजीवनी बन सके।

शिविर में कुल 1410 यूनिट रक्त संग्रहित

झुंझुनू, (निसं)। हितेष फाउंडेशन सोसायटी व नवयुवक मंडल सीतसर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय हितेष बुझमिया की छठवीं पुण्यतिथि पर वार्ड नंबर 13 स्थित सामुदायिक विकास भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हितेष के वदाजी चौधरी नाथराम बुडानिया द्वारा किया गया। शिविर में राजकीय बीडीके अस्पताल के ब्लड बैंक सहित अन्य कई निजी अस्पतालों की ब्लड संग्रहण टीमों द्वारा रक्तदान शिविर में सहयोग प्रदान किया गया। शिविर में रक्तदान के लिए युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। शिविर में कुल 1410 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। वहीं झुंझुनू जागृति मंच की ओर से आयोजित जीवन सुरक्षा एवं जन जागरुकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हादसों में घायलों की मदद करने का संकल्प करवाया गया। इस दौरान बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉ. जितेंद्र भांबू भी उपस्थित रहे। संस्थान की ओर से रक्तदान कर शिविर को सफल बनाने वाले सभी युवाओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। हितेष फाउंडेशन की ओर से राजकृष्ण लोचल ने रक्तदान करने वाले युवाओं व शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान प्रमोद बुडानिया, अंकित, विकास, अजय, राहुल, सरवन, प्रकाश, संजय, राकेश, सुनिल, अनिश, हेमंत, राजपाल व बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व युवा साथी उपस्थित रहे।

शिविर 25 को

रतनगढ़, (निसं)। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट ,रंकारा आई हॉस्पिटल व जिला अंतर्गत निवारण समिति, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में श्री भंवरलाल विनितादेवी बौद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 36वा निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेस प्रत्यारोपण शिविर 25 फरवरी 2026 बुधवार को माहेश्वरी भवन, रामचंद्र पार्क के पास होगा।

आम सूचना

बर्लामुसरा को सुनि्त किया जात है कि M.S. BALAJI TILES WORK NO.32 NEAR KMD HOSPITAL SURAJGARH BAYPASS ROAD CHIRAWA. झुंझुनू फर्म पंजीयन क्रमांक RF/JUN 2023/3184 दिनांक 20/08/2023 द्वारा रजिस्ट्रार अंतर्गत फॉर्म सुंझुनू के प्लाट पंजीकृत है उसे फॉर्म में श्रीमान राखतरव Sio श्री मुनरुचं सिंह साहोबदार है जो की 21 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रार हो गए और उनकी साहोबदारी से पहले साहोबार अर्जित कुमार Sio श्री संत कुमार ने तो है। नई साहोबदारी अर्जित कुमार Sio श्री संत कुमार और सुखीराम Sio नारायण सिंह के मध्य रहेगी। किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म सुंझुनू के यहां अतिरिक्त उर्दी करवा सकता है।

बेदखली सूचना

मनके कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश एवं सुमित्रा पत्नि कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील राजगढ जिला सुंझुनू के है जो निम कर्तन शायद पूर्वीक व्यवन करके है कि 1. यह कि परीक्षण हमारी पुत्री है, हमारी उक्त पुत्री ने हमारी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ शादी करके हमारे से अलग रह रही है, इसलिए हमने आज दिनांक 09.02.2026 को हमारी उक्त पुत्री गरीमा को हमारी व हमारे परिवार की सम्पूर्ण त्त व अलग जागदद व सम्पति से बेदखल कर दिया है, आज के हमारी उक्त पुत्री का हमारी किसी भी प्रकार की सम्पति व जागदद में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।आज के बाद हमारी उक्त पुत्री के द्वारा किये जाने वाले किसी प्रकार के कोई लेन-देन के ज़िम्मेदार हम नहीं होगे, लेन देन करने वाले स्वयं जिम्मेदार होंगे, हमारे घर व परिवार से इस्का कोई लेन देन नहीं करे है। आज के बाद हमारी उक्त पुत्री को हमारी व हमारे परिवार की कोई किसी प्रकार की भी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम सब सदस्यगण को सुनि्त करके है कि सुनि्त हो। दिनांक-09-02-2026

राधयप्रहिला-कृष्ण कुमार एवं सुमित्रा

विवादको के स्थिरीकरण के लिए समन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय बनाम कलेक्टर महोदय, नवलगढ हरिराम सनाय मोहनी देवी वगैरह बड़ पत्र बाबत उद्योगपार्श्व, रिफाईं दुस्कर्ती, विभाजन व स्थाई व्वादेश एं, धारा 88, 53, 188 राजस्थान कायस्कर्ता अधिनियम 1955

वाद सं. 84/2025

1. फूलचन्द पुत्र रामपाल निवासी ठाणम नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति8

2. भागोती देवी पत्नी मेघाराम निवासी सभा नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति-1

3. रामनिवास पुत्र भगवाना निवासी ग्राम नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति-10

4. बिजेश रणगा पुत्र अमरचन्द निवासी सभा नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति-18

5. उकारमत पुत्र कजोडमल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति 24

6. नरेंद्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज. प्रति-25

7. रामदेव सिंह पुत्र महादेवाराम निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति 28

8. सरदार सिंह पुत्र डाबर सिंह निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति 29

9. 10. बनवारीलाल पुत्र रामसिंह निवासी देवागं तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति-30

मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति 42

11. राधेश्याम पुत्र पूर्णमल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति 55

12. विजय कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला सुंझुनू राज.।

प्रति-58

वादी ने आपके विरुद्ध दावा बाबत उद्योगपार्श्व, रिफाईं दुस्कर्ती, विभाजन व स्थाई व्वादेश के लिये वाद पंजीकृत किया है। आपका इस न्यायाचार में तारीख 10 मार्च 03. सन् 2026 को दिन में 10.00 बजे को दाले का उतर देने के लिये उपसंज्ञात (हाजिर) होने के लिये वचना दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे पीडर द्वारा उपसंज्ञात हो सकते है जिसे सम्यक् अनूदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का दस्तवेज साथव दस्तवेज करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कले में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुरग्राई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कले व शक्ति में हो आपका प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के सम्बंध में साक्ष के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उपलब्धित समय के बाद उपावर्द की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंज्ञात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद तः 5 मार्च 2 सन् 2026 को हरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

प्रस्तुतकार-सहायक कलेक्टर महोदय नवलगढ

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक

मैजिस्ट्रेट नवलगढ

प्रदेश में 91 लाख से अधिक जरूरतमंदों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा का कवच हुआ मजबूत

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, समावेशी और जनकल्याणकारी नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है। प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक संवल प्रदान करते हुए उनके लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही हैं। इन योजनाओं से वर्तमान में प्रदेशभर में 91 लाख 83 हजार से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने 5 जून 2024 को नियमों में संशोधन कर पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

बनाई। इन नियमों के सतत क्रियान्वयन से वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को नियमानुसार पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से

■ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो रहा सुनिश्चित : भजनलाल शर्मा

कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इसकी अनुपालना में पेंशन की आवेदन प्रक्रिया को सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सके। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से संचालित किया जा रहा है। पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। साथ ही, पेंशन से संबंधित शिकायतों का भी

त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 366 करोड़ रुपये की राशि चार किशतों में जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निश्कत पेंशन योजनाएं भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

बुजुर्गों को संभालो वरना भविष्य में सामाजिक संकट पैदा होगा : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि “ भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली ने वर्तमान में उन्हें असहाय और उपेक्षित बना दिया है।”

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों की भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली ने वर्तमान में उन्हें असहाय और उपेक्षित बना दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा है कि वह प्रदेश में संचालित वृद्धाश्रमों का दौरा कर अदालत में 15 फरवरी को रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने कहा कि प्राधिकरण देखे की क्या इन वृद्धाश्रमों की इमारत राज्य सरकार ने बनाई है और इनमें रहने वाले क्या वरिष्ठ नागरिक हैं। इसके साथ ही अदालत ने बताया को कहा है कि इनमें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं और क्या

सरकार इन्हें कोई वित्तीय सहायता दे रही है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश लोक उत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वृद्धाश्रम केवल कागजों में नहीं हो सकते। यहां रहने वाले बुजुर्गों को पूर्ण सम्मान, बेहतर चिकित्सा और सुरक्षा के साथ मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सिर्फ परिवार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों के

मुकाबले अधिक है। वहीं तीस फीसदी बुजुर्ग महिलाएं और 28 फीसदी बुजुर्ग पुरुष गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है, लेकिन वहां तुलनात्मक रूप से सुविधाएं सीमित हैं। अदालत ने यह भी कहा कि साल 2022 में देश में 10.5 फीसदी सीनियर सिटीजन थे, जो 2050 में बढ़कर करीब 20.8 फीसदी हो जाएंगे। इसके अलावा साल 2046 तक देश की बुजुर्ग आबादी 14 साल तक के बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ऐसे में बूढ़ी आबादी को सामाजिक संवल की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया गया कि जयपुर में 4 वृद्धाश्रम सहित प्रदेश में

कुल 31 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितिन सोनी ने कहा कि राज्य सरकार कई पुनर्वास केंद्रों को वृद्धाश्रम बता रही है, जबकि वास्तव में इतने वृद्धाश्रम संचालित नहीं हो रहे हैं।

इस पर अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। पूर्व में अदालत ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका निस्तारण कर दिया था, लेकिन बाद में पालना नहीं होने पर अदालत ने मामले में पेश अवमानना याचिका को पुनः जनहित याचिका के तौर पर सुनना तय किया था।

राज्य बजट से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिनों का शक्ति प्रदर्शन



प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 22 गोदाम पर एकत्रित होकर धरना दिया।

नर्सरी शिक्षक का दर्जा देने, ग्राम साथिनों के लिए पद और आरक्षण की मांग की है। इसके साथ ही महिला भूमि को कैपस्टन मीटर प्रा. लि. को और भविष्य को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनदेखा की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों की मेहनत और योगदान अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उद्देश्य केवल न्यायालय के आदेश को लागू करना नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी और ग्राम साथिनों के अधिकारों और भविष्य को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनदेखा की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों की मेहनत और योगदान अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

नीरज जैन होंगे मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित



जयपुर।

राजस्थान के राज्यपाल हरीभाऊ बागडे बुधवार को प्रातः 9 बजे जयपुर के जगतपुरा स्थित स्काउट गाइड के राज्य प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी समारोह की अध्यक्षता करेंगे एवं राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर प्रदेश स्काउट गाइड संगठन के जनसंपर्क प्रभारी एवं विभागीय मासिक पत्रिका के सहायक संपादक नीरज जैन अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के फलस्वरूप राज्यपाल के कर कमलों से मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित होंगे। जैन की उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय सेवाओं के फलस्वरूप इस अवार्ड के लिए राज्य अवार्ड कमेटी द्वारा उनका चयन किया गया है। जैन इससे पूर्व भी अनेक साहित्यिक एवं कला मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं।

“ज्वैल्स ऑफ इंडिया” की विवादित भूमि आवंटन प्रकरण में जनहित याचिका खारिज की हाईकोर्ट ने

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि “भूमि आवंटन और भू-रूपांतरण में कोई अनियमितता नहीं हुई।”

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक रोड पर कैपस्टन मीटर को औद्योगिक उद्देश्य के लिए दी गई 205 बीघा जमीन की लीज शर्तों की अवहेलना करने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से जमीन वापस नहीं लेने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. जयनारायण त्रिवेदी की पीआईएल पर दिए।

अदालत ने कहा कि वह जमीन आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट है। अदालत में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने राज्य सरकार की ओर से पेरवी की थी। उन्होंने कहा कि, यह भूमि 1965

■ जबकि याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद का कहना था कि “राज्य सरकार ने वर्ष 1965 में गोपालपुरा पुलिसिया के पास 205 बीघा भूमि कैपस्टन मीटर प्रा. लि. को औद्योगिक उद्देश्य के लिए लीज पर दी थी। लीज शर्त के मुताबिक जमीन आवंटन का उद्देश्य पूरा नहीं होने पर भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।”

तक संस्थानिक भूमि थी, इसके भू-रूपांतरण और अवाप्ति में किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं हैं। इस प्रकरण में जयपुरिया परिवार की ओर से अधिवक्ता सुरुक्ष कासलीवाल पेश हुई थी।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1965 में गोपालपुरा

पुलिया के पास स्थित इस 205 बीघा भूमि को कैपस्टन मीटर प्रा. लि. को औद्योगिक उद्देश्य के लिए लीज पर दिया था। लीज में यह शर्त थी कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन लीज पर दी गई है, अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो जमीन स्वतः ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इसके अलावा लीज दस्तावेजों से स्पष्ट है कि यह भूमि आवंटन न तो

किसी अन्य उपयोग में लेगा और ना ही हस्तांतरित कर सकेगा। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद भी जमीन के कुछ हिस्से को मैसर्स जय डिव्हंस प्रा. लि. को सब-लीज पर दे दी गई। दोनों कंपनियों के निदेशक भी एक ही जयपुरिया परिवार से संबंध रखते हैं। इस भूमि के एक हिस्से में उच्च अधिकारियों और राजनेताओं की शह पर ज्वैल्स ऑफ इंडिया नाम से रिहायशी फ्लैट्स की बहुमंजिला इमारत बना दी गई। याचिका में यह भी कहा गया कि बिल्डर के दबाव में इस जमीन के व्यावसायिक उपयोग की भी अनुमति दे दी गई। जेडीए के तत्कालीन विधि निदेशक अपनी विस्तृत टिप्पणी में इस कृत्य को भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हुए

समय पर पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीकें अपनाकर व्यवस्था मजबूत की जाएं : वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव ने ली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा बैठक

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण

■ पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पेंशन योजना के लाभार्थियों का एनालिटिक डैशबोर्ड तैयार कर पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने और पेंशनर के भुगतान में हो रहे विलंब के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर इसको नियमित करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वी. श्रीनिवास ने कहा ने विशेष योग्यजन श्रेणी के पेंशनर का दिव्यांगता



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक ली।

प्रमाण पत्र बनने में हो रही कठिनाई के समाधान के लिए स्वावलंबन पोर्टल की टीम से संपर्क कर यथाशीघ्र समाधान करवाने, पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए वर्तमान में प्रचलित फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप को और अधिक प्रसारित कर

अधिक अधिक संख्या में पेंशनर का सत्यापन इसके माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपणां अरोड़ा, निदेशक आशीष मोदी

सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी, राजस्थान जनआधार प्राधिकरण, एनआईसी, राजस्थान विशेष योग्यजन निदेशालय तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनवरी की जिला रैंकिंग में झुंझुनूं और हनुमानगढ़ अव्वल रहे

जिला रैंकिंग से मजबूत हो रही स्कूल शिक्षा में जवाबदेही और सुधार प्रक्रिया

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी-2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग प्रदेश के समस्त जिलों के शैक्षणिक परिणामों, विद्यालयों के दैनिक संचालन और गवर्नैस संकेतकों में प्रदर्शन का समग्र आकलन करती है। ताजा रैंकिंग में झुंझुनूं और हनुमानगढ़ शीर्ष जिलों में शामिल रहे हैं, जबकि चूरू ने सराहनीय प्रयास करते हुए तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है।

रैंकिंग में छात्रों की नियमित उपस्थिति, कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता, फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी और शैक्षणिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन जैसे प्रमुख मानकों को शामिल किया गया है। सीखने के परिणामों पर बढ़ते जोर और उच्च स्तर पर नियमित प्रदर्शन समीक्षाओं के साथ, जिला रैंकिंग स्कूल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही, लक्षित सहयोग और निरंतर सुधार लाने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। इस वर्ष शैक्षणिक सीखने के परिणामों को औपचारिक रूप से रैंकिंग का हिस्सा बनाया गया है। कॉम्पैट-सी-

■ डेटा-आधारित समीक्षा से सीखने के परिणामों पर बढ़ा फोकस

बेस्ड असेसमेंट (सीबीए), ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ओआरएफ) असेसमेंट और बोर्ड परीक्षा के नतीजों को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि जिलों का प्रदर्शन न केवल प्रशासनिक दक्षता बल्कि शैक्षणिक प्रभाव को भी दर्शा सके।

एकेडमिक रैंकिंग का उद्देश्य जिलों के प्रदर्शन की नियमित, डेटा-आधारित समीक्षा करना और स्कूल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत बनाना है। जिला रैंकिंग और पैरामीटर-वाइज स्कोर की हर महा स्कूल शिक्षा विभाग (सीएसई) के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठकों में गहन समीक्षा की जाती है, जिसमें कमियों की पहचान कर सुधार के लिए स्पष्ट अगले कदम तय किए जाते हैं। ताजा रैंकिंग के अनुसार झुंझुनूं और हनुमानगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। तीसरे पायदान पर चूरू रहा, जिसने गंगानगर को पीछे

छोड़ा। सीकर, भरतपुर और खैरतल-तिजारा क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहे। बांसवाड़ा और जैसलमेर सबसे निचले पायदान पर है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जिला रैंकिंग ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। सीखने के परिणामों को रैंकिंग से जोड़ने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्तर पर निर्णय विद्यार्थियों की वास्तविक प्रगति के आधार पर हों। हमारा लक्ष्य है कि सभी जिलों को समान अवसर, समयबद्ध सहयोग और आवश्यक संसाधन मिलें, ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे।

स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल का कहना है कि डेटा-आधारित समीक्षा के परिणामों पर फोकस से अब स्कूल शिक्षा प्रणाली में ठोस और स्थायी सुधार दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में तकनीकी, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचारों के जरिए हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

मां ने बेटी को संतान मानने से किया इनकार

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में मां की ओर से याचिकाकर्ता को अपनी बेटी मानने से इनकार करने पर अदालत ने डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी को जबर्न डीएनए परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह परीक्षण से इनकार करती है तो अदालत परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगा सकती है। जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश बेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि डीएनए जांच से व्यक्ति को निजता प्रभावित होती है, लेकिन सत्य का पता लगाना भी कोर्ट का दायित्व है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता बेटी ने साल 2014 में अपने स्वर्गीय पिता की ओर से अपने बेटे के पक्ष में बनाई वसीयत को निरस्त घोषित करने और संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार देने की गुहार की। बेटी की ओर से कहा गया कि यह वृत्तक संपत्ति

होने के कारण उसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे और मां ने याचिकाकर्ता को मृतक की बेटी मानने से इनकार कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मां और भाई का डीएनए टेस्ट का उसके डीएनए से मिलाने कराने की गुहार की। इस प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार की। जिसका विरोध करते हुए मां की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि मां स्वयं ही कह रही है कि उसने याचिकाकर्ता को जन्म नहीं दिया। वहीं डीएनए परीक्षण से निजता प्रभावित होगी। इसलिए डीएनए परीक्षण की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका डीएनए जांच कराई जाए। यदि इस दौरान मां इनकार करे तो निचली अदालत परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगा सकती है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता के निवास पर पहुंचकर उनकी माता स्व. कमला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही शोक संतप्त परिवारजनों को ढाढस बंधाया।

